

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पशुपालन अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 17 मई, 2010

विषय- वित्तीय वर्ष 2010-11 में डेरी विभाग को आयोजनेत्तर में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-936/XV-2/1(01)/06, दिनांक 09 अप्रैल, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में आयोजनेत्तर अवचनबद्ध मदों में डेरी विकास विभाग को निम्नलिखित मदों में कुल रूपया 820 (रुपये आठ लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रु0 हजार में)

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
04-यात्रा व्यय	150
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100
07-मानदेय	15
08-कार्यालय व्यय	110
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50
12-कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	50
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	50
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	150
44-प्रशिक्षण व्यय	25
45-अवकाश यात्रा व्यय	25
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50
योग-	820

1. निदेशक, डेरी विभाग द्वारा सम्बन्धित जिलास्तरीय अधिकारियों को अपने स्तर से फॉट कर सम्बन्धित को सूचित करते हुये सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।
2. निदेशक, डेरी द्वारा बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-13 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को प्रत्येक माह की अगली 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।
3. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

4. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्च्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
 5. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) विभाग अनिवार्य रूप शासन को उपलब्ध करायेंगे, जिससे राज्य स्तर पर कैशफलों निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हों।
 6. किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम अधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व होगा।
 7. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।
- 2-उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-00-आयोजनेत्तर-001-निर्देशन तथा प्रशासन-03-दुग्ध सप्लाई अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-28(NP) /वित्त-4/2010, दिनांक 29 अप्रैल, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या- 1219 /XV-2/1(01)/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मंत्री, दुग्ध विकास को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
3. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने हेतु।
4. स्टाफ ऑफिसर-अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त को अवगत कराने हेतु।
5. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निर्देशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।